ably to this demand. Yet, once again no concrete action followed on the part of Government.

The inclusion of these communities among the Scheduled Tribes will be the touchstone of the commitment of any Government to social progress and uplift of weaker sections of that territory. The Government of the Union Territory has recommended that pending inclusion of these communities among the Scheduled Tribes at least the benefits availabe to other backward classes be made available to them. I urge the Home Ministry to accord sanction for giving the benefits available to other backward classes to the above communities without further delay and also to consider the case for their inclusion among the Scheduled Tribes speedily and sympathetically.

15.40 hrs

[SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*]

(vii) NEED FOR DECLARING THE KHAD AREA OF SAHARANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH AS A BACKWARD AREA

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : चेयरमैन साहब, मैं रूल न० 377 के तहत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके खाड़ की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पांच गांव आग में मुक्कमल तौर पर जल गये हैं। यह इलाका जिला सहारनपुर में है। लोगों को पीने के पानी के लिए दस-दस मील जाना पड़ता है। इस इलाके में कोई जरिया आमद व रफ्त का नहीं है। कोई सडकें नहीं हैं कोई इंडस्ट्री नहीं है। इस इलाके में अभी हाल में यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम के मिलने के बाद इस इलाके को उम्मीद बंधी है कि इस को पिछडा इलाका डिक्लेयर करके इस इलाके में रहने वालों को भी जिन्दगी की सहूलियत दी जाये ताकि वे भी जिन्दगी के दिन इत्मीनान से गुजार सकें।

شری رشید مسعود (سہارنپور) : جناب چیئرمین صاحب - میں رول نمبر ۳۷۷ کے تحت سرکار کا دھیان اتر پردیش کے سب سے پچھڑے علاقے کھاڑ کی طرف دلانا چاہتا ہوں جہاں پانچ گاؤں آگ سے مکمل طور پر جل گئے ہیں - یہ علاقہ ضلع سہارنپور میں ہے لوگوں کو پینے کے پانی کے لئے دس دس میل جانا پڑتا ہے - اس علاقے میں کوئی ذریعہ آمد و رفت کا نہیں ہے کوئی سڑکیں نہیں ہیں کوئی انڈسٹری نہیں اس علاقے میں ابھی حال میں یورینیم بھی پایا گیا ہے - یورینیم کے ملنے کے بعد اس علاقے کو امید بندھی ہے کہ اسکو پچھڑا علاقہ ڈکلیئر کر کے اس علاقے میں رہنے والوں کو بھی زندگی کی سہولیات دی جائیں تاکہ وہ بھی زندگی کے دن اطمینان سے گزار سکیں -]

(viii) DEMAND FOR PROVIDING ADEQUATE TRAIN SERVICES FOR THE LANDLESS LABOURERS OF BIHAR AND WEST U.P. GOING TO HARYANA AND PUNJAB DURING HARVESTING SEASON

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय बिहार व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों का फसल कटाई के लिए पंजाब व हरियाणा में भारी तादाद में आना शुरू हो गया है। ये मजदूर हर वर्ष फसल कटाई के वक्त ही भारी तादाद में अपने घरों को छोड़कर कपडे में सत्तू बान्धकर व कम वस्त्र पहने हुए निकल पड़ते हैं। ये मजदूर रेलगाड़ी के खचाखच भरे डिब्बों में आते हैं। यदि इन्हें डिब्बे में जगह नहीं मिलती

[श्री जगपाल सिंह]

तो वे पायदानों पर खडे होकर या छतों पर बैठकर आते हैं। कुछ तो डिब्बों के बीच के स्थान पर बैठे देखे जा सकते हैं। विगत वर्षों का अनुभव बताता है कि हर वर्ष काफी संख्या में ये मजदूर छतों से गिर कर व पायदानों से गिरकर मर जाते हैं। लेकिन आज तक सरकार ने इन के लिए विशेष रेल सेवा प्रदान करने पर विचार नहीं किया हैं। साथ ही जब ये मजदूर भारी संख्या में पंजाब के विभिन्न स्टेशनों पर जाकर के उतरते हैं तो रेलवे कर्मचारी भी इन को तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर परेशान करते हैं। इतना ही नहीं बड़े जमींदारों व किसानों के एजेंट इनको झूठी शर्तों से बहका कर ले जाते हैं और इनके साथ सरकार के सभी कानूनों को ताक पर रख कर अन्याय किया जाता हैं। यहां तक कि इन को निम्नतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन/मजदूरी भी नहीं दी जाती है।

अतः मैं सरकार का इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर ध्यान दिलाता हूं और आग्रह करता हूं कि इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय से आवश्यक सुविधा प्रदान करायें और श्रम मंत्रालय भी इनकी समस्याओं पर विचार करके कानून के अनुसार सेवा-शर्तें तय कराने का कष्ट करें।

(ix) CANCELLATION OF DELHI AS EXAMINATION CENTRE FOR INTERMEDIATE EXAMINATION BY BOARD OF SECONDARY EDUCATION, BHOPAL, M.P.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna): Mr. Chairman, Sir, The Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal announced its decision to set up Delhi as an Examination Centre for the Intermediate Correspondence Course students in its advertisement in Madhya Pradesh Chronicle dated 29-8-80 and also in several other newspapers. This was done by the Board so that the students would not have to incur all the expenditure involved in going from Delhi to Madhya Pradesh and for their stay there during the duration of the examinations. Relying on this assurance of the Board, approximately 5,500 students got themselves enrolled, opting Delhi as Examination centre.

Now the students have received their roll numbers from the Board according to which Delhi has been deleted as an Examination centre and the students instead have been allotted different centres in Madhya Pradesh itself. This is a clear violation of a commitment made by the Board and all these 5,500 examinees (which also includes a sizeable number of girl students) will be put to great inconvenience and will have to bear large expenditure in travelling from Delhi to the places of the Examination centres and in making arrangements for their stay and food during the period of the examination. As the examination commences from 1st May, 1981, it needs special attention of the Ministry of Education, so that the interests of the students from Delhi are safeguarded.

(x) DEMAND FOR SHIFTING THE HEADQUARTERS OF ASSISTANT ENGINEER (P&T) FROM GORAKHPUR

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव): समापति महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं—गोरखपुर जनपद से डाक एवं तार से सम्बन्धित सहायक अभियंता, सिविल विंग के मुख्यालय को दूसरी जगह ले जाने के सम्बन्ध में मैं आप के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो संचार के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। कई वर्षों से यहां पर उक्त समस्या हेतु मुख्यालय तथा अन्य कर्मचारियों के रहने के लिए निवास स्थान बनाने के लिए काफी भूमि खरीद ली गई है। चूंकि उक्त क्षेत्र में दो वर्षों से काम चल रहा है और अभी काफी काम